TYTLER): (a) to (d) Although the company has been incurring losses on account of heavy wage bills, low level of productivity, inadequacy of orders and conventional/outdated production facilities, yet, keeping in view the extent resource crunch, the Committee constituted, in addition to evaluate the efficacy of action plan, containing short term measures, as suggested by company, has specifically been asked to suggest any other measures, requiring no or least financial input to render the company viable.

Although productivity norms were one of the recommendation of an expert group, these could not be implemented as their recommendations were not accepted by the Government.

(e) It is a continuing process to fill up the managerial level posts through normal channel of recruitment, as and when vacancies arise.

केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि

6329. श्री महेश्वर सिंह: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी; और

(ख) सड़कों के निर्माण के लिए राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा ऐसी प्रत्येक सड़क का नाम क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) 58.24 करोड़ रु०।

(ख) केन्द्र सरकार सड़क निधि से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एक मुश्त (लम्प ग्रांट) आधार पर निधियां आवंटित करती है न कि स्कीम-वार। 1994-95 में राज्य-वार उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(लाख रु०)

क्र०सं०	राज्य/संघ का नाम	स्वीकृत प्रदेश	1994-95 में जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश		600.00
2	अरुणाचल प्रदेश		शून्य
3	असम		42.00
4	बिहार		166.00
5	गोवा		शून्य
6	गुजरात		835.00
7	हरियाणा		55.00
8	हिमाचल प्रदेश		239.00
9	जम्मू कश्मीर		250.00
10	कर्नाटक		35.00
11	केरल		50.00
12	मध्य प्रदेश		268.00
13	महाराष्ट्र		104.00
14	मणिपुर		236.00
15	मेघालय		1100.00
16	मिजोरम		शून्य
17	नागालैण्ड		7.00
18	उड़ीसा		11.00
19	पांडिचेरी		34.00
20	पंजाब		28.00
21	राजस्थान		शून्य
22	सिक्किम		259.00
23	तमिलनाडु		103.00
24	त्रिपुरा		8.00
25	उत्तर प्रदेश		505.00
26	पश्चिम बंगाल		1.00
27			157.00
28			56.00

Road side scheme of National Highways

6330. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a Motel-cum-Workshop-cum-Restaurant and retails out-let was announced under Road Side Scheme of